Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN: 2584-184X

Research Article

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शैक्षिक वातावरण पर प्रभाव

AUTHOR(S): हेमलता चौधरी

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.22744898

सारांश

शिक्षा प्रत्येक समाज का आधार होती है। शिक्षा की प्रकृति के माध्यम से ही समाज की प्रकृति का आंकलन किया जाता है। भारत को विश्वगुरु कहा गया है क्योंकि शिक्षा और ज्ञान का उद्भव, विकास और संचार यहीं से प्रारंभ हुआ। कई शताब्दियों में कई संस्कृतियों के सम्मिश्रण से भारतीय शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन होता रहा है। स्वतंत्रता के उपरांत **21**वीं सदी में नयी शिक्षा नीति **2020** लागू हो चुकी है। इसका समाज के प्रत्येक क्षेत्र पर प्रभाव होने वाला है। प्रस्तुत शोध पत्र में यह जानने का प्रयास किया गया है कि यह शिक्षा नीति शैक्षिक वातावरण के किन आयामों को प्रभावित करने वाली है। विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि नवीन शिक्षा नीति द्वारा पाठ्यक्रम, नियामकों, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक वातावरण को परिवर्तित करने की पहल हो चुकी है।

मुख्य शब्द: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शैक्षिक वातावरणए एनसीईआरटी।

Article History

- **ISSN**: 2584-184X
- **Received:** 12 May 2024
- **Accepted**: 26 June 2024
- **Published:** 30 June 2024
- **MRR:**2(6) June 2024: 56-58
- **©2024, All Rights Reserved**
- **Peer Review Process:** Yes
- **Plagiarism Checked**: Yes

Authors Details

हेमलता चौधरी
शोधार्थी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय लोगों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार की गई नीतियों का एक समूह है। एनईपी मूल रूप से देश में शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक ढांचा है। इस तरह के ढांचे के आग्रह को पहली बार वर्ष **1968** में महसूस किया गया था, जिसे फिर से **1986** में संशोधित और संशोधित किया गया था। इसकी फिर से समीक्षा की गई और **1992** में समय की आवश्यकता के अनुसार अद्यतन किया गया। तब से, पूरी दुनिया और समग्र क्षेत्र में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए हैं। इसलिए, इस वर्ष, सरकार ने इन नीतियों को शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अधिक प्रासंगिक और सम्मोहक बनाने के लिए संशोधित करने का निर्णय लिया।

नीति का विश्लेषण

नई एनईपी को के-**12** स्तर से कॉलेज/विश्वविद्यालय स्तर तक प्रणाली में परिवर्तन को औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से पेश किया गया है। विकासशील परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा सामग्री अब मुख्य-अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या-समाधान कोणों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा

एनसीईआरटी द्वारा **8** वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा।

कोडिंग कक्षा 6 से शुरू की जाएगी

गणितीय सोच और वैज्ञानिक सोच स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। छात्रों को कक्षा **6** से कोडिंग करने की अनुमति दी जाएगी।

बोर्ड परीक्षा

बोर्ड परीक्षा दो भागों में आयोजित की जाएगी - वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक। इन परीक्षाओं को रटने के बजाय ज्ञान के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया जाना जाएगा। आगे बढ़ते हुए, बोर्ड मुख्य परीक्षाओं जैसे वार्षिक/सेमेस्टर/मॉड्यूलर के व्यवहार्य मॉडल भी विकसित कर सकते हैं।

© 2024 हेमलता चौधरी. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

छात्रों के लिए कोई पृथक्करण नहीं पाठ्यचर्या के संदर्भ में विज्ञान और मानविकी जैसे सीखने के क्षेत्रों में कोई लैंगिक पृथक्करण नहीं होगा।
सह-पाठ्यक्रम और पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच कोई लैंगिक पृथक्करण नहीं होगा और कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग आदि सहित सभी विषय समग्र पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे।
एनईपी **2020** कौशल विकास पर विशेष जोर देने के साथ एक समग्र, अनुप्रयोग-आधारित शिक्षा प्रणाली बनाने पर केंद्रित है जो छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करेगी।

एनईपी और उच्च शिक्षा

इसी तरह, एनईपी द्वारा उच्च शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारे सुधार और नए विकास शुरू किए गए हैं।

उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक निकाय

NEP का उद्देश्य भारत के उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना करना है जो कानूनी और चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर एकल नियामक निकाय होगा।

एकाधिक प्रवेश और निकास कार्यक्रम

कोर्स को बीच में छोड़ने की इच्छा रखने वालों के लिए कई प्रवेश और निकास विकल्प होंगे। उनके क्रेडिट अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के माध्यम से स्थानांतरित किए जाएंगे।

ऐप्स, टीवी चैनलों के माध्यम से वयस्क शिक्षा के लिए तकनीक आधारित विकल्प

वयस्क सीखने के लिए गुणवत्ता प्रौद्योगिकी आधारित विकल्प जैसे ऐप, ऑनलाइन पाठ्यक्रम/मॉड्यूल, उपग्रह-आधारित टीवी चैनल, ऑनलाइन किताबें और आईसीटी से लैस पुस्तकालय और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदि विकसित किए जाएंगे।

ई-पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे

प्रौद्योगिकी शिक्षा योजना, शिक्षण, सीखने, मूल्यांकन, शिक्षक, स्कूल और छात्र प्रशिक्षण का हिस्सा होगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध ई-पाठ्यक्रमों में शामिल होने के लिए ई-सामग्री क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी, जिसकी शुरुआत ***8*** प्रमुख भाषाओं - कन्नड़, ओडिया, बंगाली से होगी।

विदेशी विश्वविद्यालय भारत में कैंपस स्थापित करेंगे

दुनिया के शीर्ष ***100*** विदेशी विश्वविद्यालयों को एक नए कानून के माध्यम से भारत में संचालित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दस्तावेज़ के अनुसार, ऐसे (विदेशी) विश्वविद्यालयों को भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के समान नियामक, शासन और सामग्री मानदंडों के संबंध में विशेष छूट दी जाएगी।

सभी कॉलेजों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (छज्।) द्वारा आयोजित होने वाले सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा। परीक्षा वैकल्पिक होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश की उच्च शिक्षा प्रणाली पर सकारात्मक और दीर्घकालीन प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
तथ्य यह है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की अनुमति दी जाएगी, सरकार द्वारा एक सराहनीय पहल है। इससे छात्रों को अपने ही देश में शिक्षा की वैश्विक गुणवत्ता का अनुभव करने में मदद मिलेगी। बहु-अनुशासनात्मक संस्थानों को शुरू करने की नीति कला, मानविकी जैसे हर क्षेत्र पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करेगी और शिक्षा के इस रूप से छात्रों को समग्र रूप से सीखने और बढ़ने में मदद मिलेगी। इस प्रकार, छात्र मजबूत ज्ञान आधार से लैस होंगे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश की उच्च शिक्षा प्रणाली पर सकारात्मक और दीर्घकालीन प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। तथ्य यह है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की अनुमति दी जाएगी, सरकार द्वारा एक सराहनीय पहल है। इससे छात्रों को अपने ही देश में शिक्षा की वैश्विक गुणवत्ता का अनुभव करने में मदद मिलेगी। बहु-अनुशासनात्मक संस्थानों को शुरू करने की नीति कला, मानविकी जैसे हर क्षेत्र पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करेगी और शिक्षा के इस रूप से छात्रों को समग्र रूप से सीखने और बढ़ने में मदद मिलेगी। इस प्रकार, छात्र मजबूत ज्ञान आधार से लैस होंगे।
सिंगल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की शुरुआत एक और सकारात्मक कदम है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं के तनाव को कम करेगा और उनमें से कई की तैयारी के दबाव को कम करेगा। यह आगे बढ़ने वाले सभी छात्र आवेदकों के लिए एक स्तरीय खेल का मैदान भी सुनिश्चित करेगा। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) की स्थापना निश्चित रूप से अकादमिक क्रेडिट को संग्रहीत करने के लिए एक मजबूत विचार है जो छात्र विभिन्न मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों से पाठ्यक्रम लेकर कमाते हैं। एक छात्र कोर्स पूरा करके अंक अर्जित कर सकता है और इन्हें एबीसी खाते में जमा किया जाएगा। अगर कोई कॉलेज बदलने का फैसला करता है तो वह इन क्रेडिट्स को ट्रांसफर कर सकता है। यदि कोई छात्र कभी किसी कारण से बाहर हो जाता है, तो ये क्रेडिट बरकरार रहेंगे, जिसका अर्थ है कि वह वर्षों बाद वापस आ सकता है और जहां से छात्र छोड़ा था वहां से शुरू कर सकता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण से यह कहा जा सकता है कि नवीन शिक्षा नीति पाठ्यक्रमों, शैक्षणिक विधियों, क्षेत्रों, उच्च शिक्षा में शैक्षिक स्तरों और विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ रोजगारपरक शिक्षा पर केन्द्रित है और इससे शैक्षिक वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव आने की संभावना दिखायी देती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रकाश कुमार. **21**वीं सदी की मांग पूरी करेगी नई शिक्षा नीति. आउटलुक हिंदी. **24** अगस्त **2020.**
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार. राष्ट्रीय शिक्षा नीति **2020.** नई दिल्ली: भारत सरकार; **2020.**

© 2024 हेमलता चौधरी. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

3. प्रो. के. एल. शर्मा. दैनिक भास्कर, जयपुर संस्करण. **24** अगस्त **2020;** पृ. **2.**
4. गंगवाल सुभाष. नई शिक्षा नीति **21**वीं सदी की चुनौतियों का करेगी मुकाबला. दैनिक नवज्योति. **22** अगस्त **2020;** पृ. **4.**
5. राजस्थान पत्रिका, नागौर. संपादकीय पृष्ठ. **28** जनवरी **2020.**
6. तन्खा वरुण, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता. राजस्थान पत्रिका, नागौर. **26** अगस्त **2020;** संपादकीय पृष्ठ.
7. सिंह दुर्गेश. क्रॉनिकल मासिक पत्रिका. मई **2020;** पृ. **80–81.**

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

© 2024 हेमलता चौधरी. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/